www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित
देश की उपासना
देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए
DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर
वर्ष – 04 | अंक – 203 | जौनपुर बुधवार, 11 मार्च 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

विपक्ष आज लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पेश करेगा अविश्वास प्रस्ताव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक, स्पीकर का व्यवहार पक्षपाती है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। कुल 118 विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्ताव तब पेश किया जाएगा जब सदन से इसकी अनुमति मिल जाएगी। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरन रिजिजू इस प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रवि शंकर प्रसाद और भरतृहरी महताब इस विषय पर अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के चिराग पासवान भी सदन को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा का जवाब दे सकते है। विपक्षी सांसद गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जोथिमानी स्पीकर को हटाने के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष लोकसभा स्पीकर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। मंगलवार को स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित है। तृणमूल कांग्रेस इसके तत्काल बाद सीईसी के खिलाफ नोटिस देने के लिए विपक्ष को लामबंद करने में जुटी है। अगर तृणमूल प्रयास में सफल रही तो पहला मौका होगा, जब संसद में सीईसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर यूकेडी कार्यकर्ता विधानसभा परिसर तक पहुंचे

गैरसैण, (एजेंसी)। उत्तराखंड में सोमवार को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) का गैरसैण स्थाई राजधानी की मांग और वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। यूकेडी कार्यकर्ता पुलिस को धत्ता देकर विधानसभा परिसर तक पहुंच गये।सोमवार को केंद्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष यूकेडी आशीष नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलग–अलग स्थानों से विधानसभा कूच किया और एक के बाद एक लगातार पांच बैरियर तोड़कर विधानसभा के मुख्य बैरियर दिवालीखाल से आगे निकल पड़े। दिवालीखाल बैरियर टूटते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पुलिस को मजबूरन पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बावजूद भी यूकेडी के कार्यकर्ता फिर भी डटे रहे और पानी की बौछारों को पार करते हुए पांचवा गेट भी तोड़कर विधानसभा की ओर निकल पड़े।पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए यूकेडी के कार्यकर्ताओं को दिवालीखाल से आधा किलोमीटर आगे ही रोक दिया। जहां पर यूकेडी कार्यकर्ता आशीष नेगी के नेतृत्व में सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।

कैबिनेट की बैठक - सीएम योगी ने 27 प्रस्तावों पर लगा सकती है मुहर

लखनऊ, (संवाददाता)। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कुल 27 प्रस्ताव रखे जाएंगे। राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए और सख्त कदम उठाने जा रही है। राज्य कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक राशि स्टाक, शेयर या अन्य निवेश में लगाने पर इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया जा रहा है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन हो रहा है। वर्तमान नियमावली में इसका कोई प्रावधान नहीं है। कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति से जुड़ा कोई लेन–देन करता है तो उसे तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। पहले

एक माह के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति का विवरण देना होता था। हर वर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपनी अचल संपत्तियों की घोषणा करनी होगी। अभी यह घोषणा हर पांच वर्ष में करने का नियम है। भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत दान की लिखत पर स्टांप शुल्क में संशोधन का भी प्रस्ताव है। कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को कानपुर शहर से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर चार लाइन पुल बनने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली और टेक्सटाइल एवं गार्मेंटिंग पॉलिसी 2022 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। कैबिनेट में परिवहन विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग, हथकरघा उद्योग, दुग्ध विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, भू तत्व एवं खनकर्म विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गृह, वित्त, ऊर्जा, समाज कल्याण और खाद एवं रसद विभाग के प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है।

लखनऊ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी सौगात, सीएम योगी के साथ करेंगे ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन

लखनऊ, (संवाददाता)। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दो दिवसीय दौरे को अंतिम रूप दे दिया है। वे शहर के नए ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह 13 मार्च को लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मंत्री 12 और 13 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में रहेंगे। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री 12 मार्च को लगभग रात 8:00 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से रवाना होने के बाद, वे रात 8:30 बजे एक पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होंगे और फिर 5–ए, कालिदास मार्ग स्थित आवास पर रात बिताएंगे। शुक्रवार, 13 मार्च को रक्षा मंत्री सुबह 11::20 बजे कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास से प्रस्थान करेंगे और सुबह 11:30 बजे सीएमएस गोल्फ सिटी, सेक्टर सी, पॉकेट 9 पहुंचेंगे, जहां वे सिटी मोंटेसरी स्कूल की गोल्फ सिटी शाखा के उद्घाटन में भाग लेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजजीपुरम स्थित विधायक

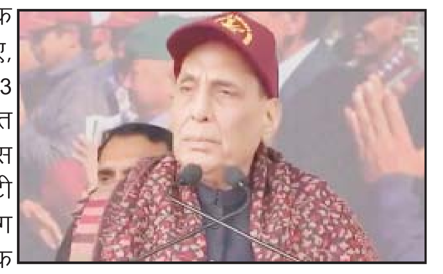

योगेश शुक्ला के आवास और राजेंद्र नगर स्थित विधायक आवास पर दिवंगत विंध्यवासिनी कुमार (पूर्व एमएलसी) के आवास पर जाएँगे। रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शाम लगभग 4:30 बजे समतमूलक चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। वे समतमूलक चौक से डालीगंज ब्रिज तक ग्रीन कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। इसके बाद वे शाम 5रू00 बजे हसनगंज स्थित झूलेलाल वाटिका में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

लोकसभा में विपक्ष पर भड़के शिवराज सिंह, बोले– ऐसी राजनीति पर शर्म आती है

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष द्वारा की गई नारेबाजी की कड़ी आलोचना की। चौहान जब केंद्र सरकार की किसान योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तब विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी।

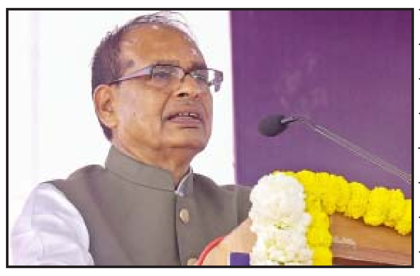

इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने कथित वोट चोरी का विरोध किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिवराज चौहान ने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों से संबंधित हैं। किसान और देश सुनना चाहते हैं, लेकिन वे (विपक्ष) नहीं चाहते कि देश सुने। विपक्ष की ऐसी राजनीति शर्मनाक है। तेल बीज मिशन और झारखंड में कृषि सहायता से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए हमने एमआईडीएच योजना शुरू की है और झारखंड सरकार को बागवानी के लिए भी सहायता मिल रही है। हम पॉली हाउस, ग्रीनहाउस और सिंचाई के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं। इसी बीच, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 50 से अधिक सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद अध्यक्ष पद पर आसीन भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद को अवकाश दे दिया। जगदंबिका पाल ने कहा कि बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है और सांसदों से प्रस्ताव पर कायम रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष ने अनुमति और प्रक्रिया में उदारता दिखाई है।

अमित शाह का पलटवार- इतना गैर-जिम्मेदार विपक्ष नहीं देखा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होते ही, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उस मंत्री के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने विपक्ष को सबसे ज्यादा बार बाधित किया। यह गोगोई के संबोधन के दौरान रिजिजू के उस बयान के जवाब में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्षी सांसदों ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया और वे इसका जवाब देंगे। इसके बाद कांग्रेस सांसद ने कहा कि भविष्य में जब संसदीय अभिलेखों और प्रतिलेखों का अध्ययन किया जाएगा, तो आंकड़े बताएंगे कि किरेन रिजिजू ही वह संसदीय कार्य मंत्री थे जिन्होंने विपक्ष को सबसे ज्यादा बार बाधित किया। रिजिजू का बचाव करते हुए

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि इस तरह की बाधाएँ तभी आवश्यक होती हैं जब कोई संसदीय नियमों का पालन नहीं करता है, और उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का उदाहरण दिया। शाह ने कहा कि मैं सहमत हूँ, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने सबसे ज्यादा व्यवधान डाला है। लेकिन हमने इतना गैर–जिम्मेदार विपक्ष भी कभी नहीं देखा। जिसका मतलब था कि व्यवधान विपक्ष द्वारा सदन के नियमों का बार–बार उल्लंघन करने के कारण थे। अपने संबोधन में, गोगोई ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा के लिए लाया गया है, न कि किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। निचले सदन को संबोधित करते हुए गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी के रूप में लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला के खिलाफ। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने आज सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 50 से अधिक सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होकर, अध्यक्ष पद पर बैठी भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद को अवकाश दिया।

ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा में डिबेट शुरू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मंगलवार को विपक्षी सांसदों के एक समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिससे सदन में पक्षपातपूर्ण आचरण के आरोपों पर बहस छिड़ गई। खबरों के मुताबिक, 118 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अध्यक्ष पर सत्ताधारी पक्ष के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप तब लगाया गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर सदन में बोलने नहीं दिया गया। बहस शुरू होते ही कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने कई वर्षों से उपसभापति नियुक्त नहीं किया है, जिससे संवैधानिक शून्यता उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि सदन को एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कार्यवाही की अध्यक्षता

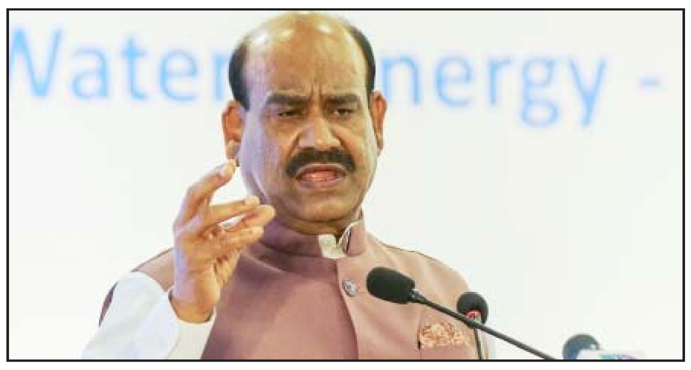

कर सके। वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने पिछले कई वर्षों से उपसभापति नियुक्त नहीं किया है, जिससे संवैधानिक शून्यता उत्पन्न हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि सदन को प्रस्ताव पर बहस के दौरान कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता कर रहे भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने सदस्यों को सूचित किया कि प्रस्ताव पर बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। उन्होंने सांसदों से अपने भाषण को प्रस्ताव के विषय तक ही सीमित रखने का आग्रह किया। पाल ने आगे कहा कि अध्यक्ष ने विपक्ष को प्रस्ताव लाने की अनुमति देकर और बहस की प्रक्रिया को सुगम बनाकर उदारता दिखाई है। पाल ने कहा कि विपक्ष के प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष ने अनुमति और प्रक्रिया में उदारता दिखाई है, और सदस्यों से समय सीमा का पालन करने और अपने भाषणों के दौरान प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित रखने का आग्रह किया। चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए आरोप निराधार हैं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत मंडपम में आहार 2026 का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को भारत मंडपम में खाद्य और आतिथ्य उद्योग के लिए दुनिया के प्रमुख बी2बी व्यापार मंचों में से एक, आहार 2026 के 40वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 10 से 14 मार्च तक चलने वाले पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले में दुनिया भर के उद्योग जगत के नेताओं, प्रदर्शकों और आगंतुकों की बड़ी संख्या में भागीदारी होने की उम्मीद है।भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और आईटीपीओ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी खाद्य, आतिथ्य और संबद्ध क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए नवाचारों को प्रदर्शित करने, अपने नेटवर्क का विस्तार करने और नए बाजार अवसरों की खोज करने के लिए एशिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों में से एक के रूप में स्थापित हो चुकी है।आहार 2026 में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चावल, समुद्री उत्पाद, मांसाहारी भोजन, रसोई उपकरण, होटल और आतिथ्य उपकरण और लघु खाद्य उद्यमों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1,800 प्रदर्शक

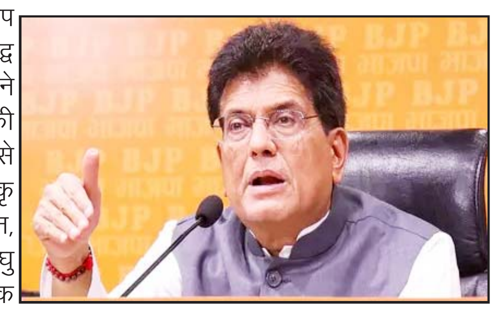

एक साथ आएंगे। इस आयोजन में 17 देशों के लगभग 155 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों के भाग लेने की उम्मीद है, जो आयोजन स्थल पर लगभग 1,15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इटली को इस वर्ष के आयोजन के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है।आहार 2026 को कई उद्योग संघों का समर्थन प्राप्त हुआ है, ।

सरकार सभी हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे का विस्तार करे : राघव चड्ढा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को हवाई अड्डों पर किफायती भोजन का मुद्दा उठाया और सरकार से उड़ान यात्री कैफे पहल को देश के सभी हवाई अड्डों पर विस्तारित करने का आग्रह किया। राघव चड्ढा ने उच्च सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि हवाई यात्रियों

ने लंबे समय से हवाई अड्डों पर भोजन की उच्च लागत की शिकायत की है। चड्ढा ने कहा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी संसद में यह मुद्दा उठाया था। हालांकि, उन्होंने चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की सरकार की पहल की सराहना की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि योजना को व्यापक कार्यान्वयन और सुधार की आवश्यकता है।चड्ढा ने बताया कि भारत में वर्तमान में 150 से अधिक हवाई अड्डे हैं, लेकिन उड़ान यात्री कैफे केवल 10 से 12 हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध हैं। उन्होंने सरकार से इस पहल का विस्तार करने का आग्रह किया ताकि देश भर के प्रत्येक हवाई अड्डे पर यात्रियों को किफायती भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध हो सकें। सांसद ने चेक–इन और सुरक्षा जांच के बाद प्रस्थान क्षेत्र में इन कैफे को स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जहां यात्री अपनी उड़ान में सवार होने के लिए सबसे अधिक समय प्रतीक्षा करते हैं। उनके अनुसार, यात्री इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान चाय या नाश्ता खरीदने की अधिक संभावना रखते हैं।उन्होंने कहा कि फिलहाल, ये कैफे केवल चेक–इन से पहले वाले क्षेत्र में, सुरक्षा जांच से पहले स्थित हैं।

घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य- वेद गुप्ता

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई सुचारु रखने को लेकर अफसरों और एजेंसी संचालकों की बैठक की गई।विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस विषय में मुख्यमंत्री से वार्ता कर अयोध्या में कमर्शियल सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा। सर्किट हाउस में गैस एजेंसी संचालकों, इंडियन ऑयल के अधिकारियों एडीएम सिटी योगानंद पाण्डेय तथा जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश मिश्र के साथ बैठक कर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में कमर्शियल सिलेंडरों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया।विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही स्पष्ट कर चुके हैं कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।विधायक ने कहा कि अयोध्या एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी है और आने वाले दिनों में रामनवमी का पर्व भी निकट है। ऐसे में शहर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में संतों और महंतों के यहां नियमित रूप से भंडारे आयोजित होते हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में शहर में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है, विशेषकर 19 मार्च को बड़ी संख्या में लोगों के आगमन की उम्मीद है।विधायक ने स्पष्ट किया कि घरेलू सिलेंडरों की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग घबराकर गैस एजेंसियों पर लाइन लगा रहे हैं।इससे उपभोक्ताओं के साथ–साथ गैस डीलरों को भी अनावश्यक परेशानी हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संयम बनाए रखें।मौके पर डीलर रामू प्रियदर्शी, रतन सिंह, सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही।

संपादकीय

समाधान ढूंढना सही दृष्टिकोण

क्या अब ये बात भरोसे के साथ कही जा सकती है कि न्यायपालिका ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर ली है? आखिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की धारणा इस हद तक क्यों पहुंच गई कि पाठ्य–पुस्तक में उसका जिक्र होने लगा? एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की किताब में न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों के जिक्र से बार एसोसिएशन के साथ–साथ प्रधान न्यायाधीश भी आहत हुए। पुस्तक में जिन चुनौतियों का उल्लेख है, उनमें विचाराधीन मुकदमों की विशाल संख्या, न्यायाधीशों की कमी, और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। न्यायपालिका में इससे इतनी नाराजगी फैली कि प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत ने मामले का स्वतरू संज्ञान लिया। कहा कि कि संस्था के प्रमुख के बतौर उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य है। उधर बार एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि किताब में संसद में आपराधिक छवि के व्यक्तियों की मौजूदगी और शासन के दूसरे क्षेत्रों में मौजूद भ्रष्टाचार की चर्चा एनसीईआरटी ने क्यों नहीं की? चूंकि न्यायपालिका के पास अवमानना कार्यवाही की ताकत है, इसलिए प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणियों का तुरंत असर हुआ। एनसीईआरटी ने संबंधित किताब पर अफसोस जताते हुए उसकी बिक्री तुरंत रोक दी और उस हिस्से को हटाने का एलान किया, जिस पर विवाद खड़ा हुआ। मगर क्या न्यायपालिका से जुड़े लोग ये बात भरोसे के साथ कह सकने की स्थिति में हैं कि अब उन्होंने अपनी संस्था की प्रतिष्ठा की रक्षा कर ली है? क्या उनके लिए यह प्रश्न उठाना बेहतर नहीं होता कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की धारणा इस हद तक क्यों पहुंच गई कि पाठ्य–पुस्तक में उसका जिक्र होने लगा? क्या यह अधिक उचित एवं सकारात्मक नजरिया नहीं होता कि वे ऐसी धारणा की जड़ तक पहुंचेंगे और उसका निवारण करेंगे? इस बात से कोई इनकार नहीं है कि बात सभी जगहों पर मौजूद खामियों की होनी चाहिए। मगर एक जगह खामी है, तो उससे दूसरे स्थलों पर मौजूद बुराइयों को सही बताने का तर्क तो नहीं मिल जाता? सार्वजनिक लाभ के नजरिए से कहा जाता है कि धूप सर्वश्रेष्ठ कीटाणु नाशक है– यानी पारदर्शिता भूल–सुधार का आरंभिक उपाय है। अतरू संदेह, आरोप, या धारणाओं को दबाने की कोशिश के बजाय उनसे संबंधित तथ्यों को सामने लाना, उन पर बहस करना और जहां समस्या नजर आए उसका समाधान ढूंढना सही दृष्टिकोण माना जाएगा। और उससे ही विभिन्न संस्थाओं सहित पूरे राज्य–तंत्र की प्रतिष्ठा सुरक्षित हो सकेगी।

ब्रह्मपुत्र पर चीन का मेगा बांध विकास की परियोजना है या भारत पर रणनीतिक दबाव

नीरज

हिमालय से निकलने वाली नदियाँ केवल जलधाराएँ नहीं होतीं, वह राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के समीकरणों को भी प्रभावित करती हैं। इन्हीं नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से निकलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और फिर बांग्लादेश तक जीवनदायिनी धारा के रूप में बहती है। हाल के वर्षों में तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र पर चीन द्वारा बनाई जा रही विशाल जलविद्युत परियोजना ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह परियोजना केवल ऊर्जा उत्पादन की जरूरत से प्रेरित है या इसके पीछे भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने की योजना भी छिपी हुई है? उल्लेखनीय है कि चीन जिस परियोजना पर काम कर रहा है, उसे दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इसकी अनुमानित उत्पादन क्षमता लगभग 60,000 मेगावाट बताई जाती है, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत संयंत्र 'थ्री गॉर्जेस डैम' से भी कई गुना अधिक है। इस परियोजना पर करीब 1.2 ट्रिलियन युआन, यानी लगभग 140 से 170 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। योजना के अनुसार इसमें पाँच बड़े कैस्केड बांध बनाए जाएंगे और इससे हर साल लगभग 300 अरब यूनिट बिजली पैदा की जा सकेगी। यह बिजली उत्पादन कई देशों की कुल वार्षिक खपत के बराबर माना जाता है। यह परियोजना तिब्बत में उस स्थान के पास बनाई जा रही है जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत के आसपास एक विशाल मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भूगोल की दृष्टि से यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ नदी का प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है और गहरी घाटियाँ बनती हैं। इसी कारण इसे जलविद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। लेकिन यही भौगोलिक स्थिति भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता का कारण भी बन गई है। दरअसल ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत की जीवनरेखा है। इसका कुल प्रवाह मार्ग लगभग 2880 किलोमीटर लंबा है, जिसमें करीब 1625 किलोमीटर तिब्बत, लगभग 918 किलोमीटर भारत और करीब 337 किलोमीटर बांग्लादेश में बहता है। यह दुनिया की सबसे अधिक जलप्रवाह वाली नदियों में से एक है और मानसून के समय इसका औसत जल प्रवाह लगभग 19,800 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश की कृषि, मत्स्य पालन, जल परिवहन और पारिस्थितिकी इस नदी पर काफी हद तक निर्भर हैं। हालाँकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ब्रह्मपुत्र का अधिकांश जल भारत में ही बनता है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार नदी के कुल प्रवाह का लगभग 65 से 70 प्रतिशत हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है, जो मुख्यतः मानसूनी वर्षा और सहायक नदियों से आता है। चीन के हिस्से से आने वाला जल लगभग 22 से 35 प्रतिशत के बीच माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि चीन भले ही नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित हो, लेकिन पूरे नदी तंत्र के जल पर उसका पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है। इसके बावजूद भारत की चिंताएँ पूरी तरह निराधार नहीं कही जा सकतीं। यदि चीन नदी के ऊपरी हिस्से में बड़े पैमाने पर जल संरचनाएँ बनाता है, तो उसे पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की एक हद तक क्षमता मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह नियंत्रण कई प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि गैर–मानसून के समय पानी रोक लिया जाए तो नीचे के क्षेत्रों में जल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। वहीं यदि अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाए तो असम और बांग्लादेश में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू डेटा नियंत्रण का है। अंतरराष्ट्रीय नदियों के मामले में जल प्रवाह और मौसम से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतीत में भारत और चीन के बीच ऐसे समझौते हुए हैं जिनके तहत चीन मानसून के समय ब्रह्मपुत्र के जल स्तर की जानकारी भारत को देता है। लेकिन जब दोनों देशों के बीच सीमा तनाव बढ़ा, तब कुछ समय के लिए यह डेटा साझा करना भी बाधित हुआ। इससे यह आशंका मजबूत हुई कि जल संसाधन भी भविष्य में कूटनीतिक दबाव का साधन बन सकते हैं। इस परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएँ भी कम नहीं हैं। हिमालय का यह क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यदि किसी बड़े भूकंप या प्राकृतिक आपदा के कारण बांध को नुकसान होता है तो उसके परिणाम नीचे के देशों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। इतनी बड़ी जलराशि का अचानक बहाव असम और बांग्लादेश में गंभीर तबाही ला सकता है। दूसरी ओर, चीन इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहता है कि यह परियोजना "रन–ऑफ–द–रिवर" तकनीक पर आधारित है, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर ज्यादा

असर नहीं पड़ेगा। उसका तर्क है कि यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करने और तिब्बत क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद करेगी। दूसरी ओर भारत भी पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में भारत लगभग 76 गीगावाट जलविद्युत क्षमता विकसित करने की योजना बना रहा है, जिसमें से करीब 52 गीगावाट क्षमता केवल अरुणाचल प्रदेश में संभावित मानी जाती है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन के साथ–साथ नदी के जल प्रबंधन में संतुलन बनाए रखना भी है। स्पष्ट है कि ब्रह्मपुत्र पर चीन का यह मेगा बांध केवल एक ऊर्जा परियोजना नहीं है। यह आधुनिक दौर की "जल भू–राजनीति" का उदाहरण भी है, जहाँ नदी के स्रोत पर स्थित देश को स्वाभाविक रणनीतिक बढ़त मिल जाती है। चीन इसे विकास और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से देखता है, जबकि भारत इसे जल सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जोड़कर समझता है। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र भविष्य में सहयोग का माध्यम भी बन सकती है और तनाव का कारण भी। यदि भारत, चीन और बांग्लादेश पारदर्शी जल प्रबंधन, डेटा साझेदारी और पर्यावरणीय सुरक्षा के साझा ढाँचे पर सहमत हो जाएँ, तो यह नदी संघर्ष की धारा नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहयोग और समृद्धि की धारा बन सकती है। हालांकि लेकिन इसके लिए विश्वास, पारदर्शिता और दूरदर्शी कूटनीति की आवश्यकता होगी।

सऊदी अरब की मदद के लिए रणभूमि में उतर सकता है पाकिस्तान

नीरज

पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते सुरक्षा हालात के बीच पाकिस्तान एक बेहद जटिल सामरिक दुविधा में फंस गया है। सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने इस्लामाबाद के सामने यह कठिन सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वह अपने पुराने सहयोगी सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा या फिर क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के सऊदी दौरे ने इस बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल ईरान द्वारा सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाओं के बाद क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए सामरिक रक्षा समझौते की परीक्षा शुरू हो गयी है। इस समझौते के अनुसार यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश उसकी सुरक्षा में सहयोग करेगा। इस संकट के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने रियाद में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। इस बैठक में ईरानी हमलों और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर चर्चा की गयी। दोनों देशों ने साझा रक्षा समझौते के तहत संभावित कदमों पर विचार किया। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यदि पाकिस्तान सऊदी अरब का सैन्य समर्थन करता है तो वह सीधे ईरान के साथ टकराव की स्थिति में आ सकता है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पहले से ही अस्थिर है और ऐसे में नया संघर्ष उसके लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। मगर यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का घनिष्ठ सहयोगी रहा है। सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता और तेल आपूर्ति के माध्यम से कई बार पाकिस्तान की मदद की है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ईरान के साथ लंबी सीमा लगती है और इन दोनों देशों के बीच भी सुरक्षा और ऊर्जा से जुड़े कई हित हैं। यही कारण है कि अब तक पाकिस्तान ने इस संघर्ष में सीधे शामिल होने से बचने की कोशिश की है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस्लामाबाद खुलकर सऊदी अरब के पक्ष में उतरता है तो इससे ईरान के साथ संबंध गंभीर रूप से बिगड़ सकते हैं और सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि इस संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति भी है। देश में सुन्नी और शिया समुदाय दोनों की बड़ी आबादी है। ईरान शिया बहुल देश है जबकि सऊदी अरब सुन्नी नेतृत्व वाला राष्ट्र है। ऐसे में यदि पाकिस्तान किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करता है तो देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका भी रहेगी। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किये थे और गुस्साई भीड़ ने पाकिस्तान स्थित अमेरिकी मिशन पर हमला भी बोल दिया था। इसके बाद हालात काबू करने के लिये सुरक्षा बलों को कार्रवाई करनी पड़ी थी जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आयीं। इस घटना ने इस्लामाबाद की चिंता और बढ़ा दी है। पाकिस्तान की सरकार

को आशंका है कि यदि वह खुलकर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के समर्थन में सेना उतारता है तो देश में मौजूद शिया समुदाय भड़क सकता है और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी कारण पाकिस्तान की सरकार और सेना अब तक संतुलित नीति अपनाने की कोशिश करती रही है। इसके अलावा, पाकिस्तान की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक परमाणु शक्ति है और मुस्लिम देशों में उसकी सेना को काफी प्रभावशाली माना जाता है। यदि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ सैन्य रूप से जुड़ता है तो इससे पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसके अलावा यह संघर्ष वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल, चीन और रूस जैसे बड़े देशों के हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का कोई भी फैसला केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान फिलहाल सीधे युद्ध में शामिल होने से बचने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि सऊदी अरब पर हमले बढ़ते हैं और रक्षा समझौते के तहत दबाव बढ़ता है तो इस्लामाबाद के सामने कठिन निर्णय लेने की नौबत आ सकती है। फिलहाल असीम मुनीर की कूटनीतिक सक्रियता इसी संतुलन को साधने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। आने वाले समय में पाकिस्तान का रुख यह तय करेगा कि पश्चिम एशिया का यह संकट कितना व्यापक रूप लेता है। हालांकि सैन्य इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान की सेना आज तक किसी युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकी है। भारत के साथ हुए युद्धों सहित कई सैन्य टकरावों में पाकिस्तान को करारी हार ही मिली है। ऐसे में यदि पाकिस्तान सऊदी अरब के समर्थन में किसी संघर्ष में उतरता भी है तो उससे युद्ध के व्यापक परिदृश्य में कोई बहुत बड़ा सामरिक बदलाव आने की संभावना कम ही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की भागीदारी अधिकतर प्रतीकात्मक या सीमित सैन्य सहयोग तक ही रह सकती है, जबकि संघर्ष की दिशा मुख्य रूप से क्षेत्रीय महाशक्तियों की रणनीति से ही तय होगी।

एआई क्रांति की फसल काटने का बंदोबस्त

अजीत द्विवेदी

दिल्ली में हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत में एआई क्रांति की मजबूत आधारशिला रखने वाले कार्यक्रम साबित होगा या वक्ती मीडिया हाइप के बाद इसका भी मामला नेपथ्य में चला जाएगा और सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, जैसा पहले चलता रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अब तक हुई तमाम औद्योगिक और संचार क्रांतियों में भारत की भूमिका नगण्य रही है। पहली औद्योगिक क्रांति में भी भारत ने न कुछ आविष्कार किया और न कोई निर्माण किया। उसी तरह संचार क्रांति में भी भारत का योगदान एक यूजर देश के रूप में ही रहा। भारत ने हर क्रांति में बने उत्पादों का इस्तेमाल किया। अगर सोशल मीडिया क्रांति में भारत की उपलब्धि यह है कि भारत में सबसे ज्यादा 45 करोड़ फेसबुक यूजर हैं तो एआई क्रांति में अभी तक भारत की उपलब्धि का आंकड़ा यह है कि भारत में चौटजीपीटी के अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यूजर हैं। भारत में इनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या साढ़े 14 करोड़ है। अब दुनिया भर की एआई कंपनियों में होड़ मची है कि किसके यूजर सबसे ज्यादा होंगे। गूगल को अपने जेमिनी के यूजर बढ़ाने हैं तो सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ मीटिंग के बाद मीडिया के सामने कहा कि उनकी कंपनी भारत के दो करोड़ कर्मचारियों को एआई के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देगा। इसी तरह सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपनएआई भी चौटजीपीटी के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण देगी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 30 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। 30 साल पहले इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के ट्रेनिंग कैंप लगते थे। उनके पेशेवर भारत के लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के इस्तेमाल की जानकारी देते थे। लोगों को ईमेल और सर्च इंजन के इस्तेमाल में प्रशिक्षित किया जाता था। आज भी वही इतिहास दोहरा रहा है। आप कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलिए वहां सबसे ज्यादा विज्ञापन इस बात का आ रहा है कि एआई का इस्तेमाल करना सीखें और कमाई बढ़ाए। याद करें कैसे पहली संचार क्रांति के समय गली गली में कंप्यूटर और लैपटॉप रिपेयर की दुकानें खुलीं, उसके बाद मोबाइल हैंडसेट के रिपेयर और सिम बेचने की दुकानें खुलीं और अब हर जगह एआई सिखाने की दुकानें खुल रही हैं। सवाल है कि इसमें भारत का अपना क्या है? इसी एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की कंपनी सर्वम ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बेंगलुरू स्थित कंपनी ने पहला मल्टी बिलियन पैरामीटर का एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। आम लोगों के बीच यह नहीं पहुंचा है और न इसके पेशेवरों द्वारा लोगों को सर्वम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी ओर अमेरिका की कंपनियों के प्लेटफॉर्म करोड़ों की संख्या में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चौटजीपीटी के कई वर्जन आ गए। उसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसी तरह जेमिनी, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म का करोडों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के डीपसीक की बात छोड़ दें तो अमेरिकी कंपनियां पूरी दुनिया पर छा गई हैं। उनके यहां इस पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, जिसकी भारत में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अमेरिका अगले साल एआई पर साढ़े छह सौ बिलियन डॉलर यानी करीब छह लाख करोड़ रुपए का है। चीन अगले साल सौ बिलियन डॉलर यानी एक लाख करोड़ रुपए का है। इसके मुकाबले भारत सरकार ने इस साल बजट में एआई के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सोचें, कहां छह लाख और एक लाख करोड़ और कहां एक हजार करोड़! दुनिया के एआई पेटेंट में भारत का हिस्सा सिर्फ 0.39 फीसदी है तो चीन का हिस्सा 70 फीसदी है। भारत सरकार एक हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है लेकिन देश के अरबपतियों ने लाखों करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। इतना बड़ा ऐलान है कि अमेरिका और चीन भी चित हो जाएं। अडानी समूह ने अगले 10 साल में 18 लाख करोड़ तो अंबानी समूह ने सात साल में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया है। सोचें, यह रकम पढ़ कर लगेगा कि अब भारत एआई क्रांति का विश्वगुरू बनने वाला है। भारत को कोई नहीं रोक सकता है। यह भी भाव मन में पैदा होगा कि अमेरिका और चीन भारत के इन दो कारोबारियों के सामने क्या हैं।

नीतीश की विदाई या जदयू का सफाया

राजेंद्र शर्मा

किसी एकाधिकारी प्रकृति की, वास्तव में फासीवादी प्रकृति की राजनीतिक पार्टी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जहां गठबंधन का आधार ही किसी न किसी तरह सत्ता में हिस्सा हासिल करना होता है, न कि सहयोगी पार्टियों के साथ जनहित के किसी साझा कार्यक्रम को पूरा करना। इन तमाम वर्षों में हमारे देश में वामपंथी पार्टियों के नेतृत्व वाले गठबंधन ही बाद वाली प्रकृति के गठबंधन साबित हुए हैं नाटक के पहले अंक में, बिहार के मुख्य मंत्री पद पर बने रहते हुए, नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए चुनाव के लिए अपना पर्चा भरा। यह पर्चा भरे जाने के संबंध में दो बातें खासतौर पर गौर करने वाली थीं। पहली, यह पर्चा नीतीश कुमार की अपनी पार्टी, जदयू के मंझले दर्जे के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुखर तथा काफी व्यापक विरोध के बावजूद भरा गया। इस विरोध की शुरूआत, राज्यसभा के रास्ते से नीतीश कुमार की बिहार से विदाई की खबरें आने के साथ ही हो गयी थी। वास्तव में इस मुखर विरोध को शांत करने के लिए और बिहार से अपनी विदाई के लिए, बिहार में गठजोड़ सरकार में अपनी सहयोगी, भाजपा को अपने समर्थकों का निशाना बनने से बचाने के लिए, नीतीश कुमार ने यह अजीबो–गरीब बयान भी दिया था कि उनकी ही इच्छा थी कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी देश की सेवा करें। वैसे बिहार में सरकार और पार्टी को उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जाहिर है कि उनके इस बयान का कम से कम जदयू कार्यकर्ताओं की निराशा पर कोई असर नहीं पड़ा। हां! भाजपा को जरूर आलोचनाओं से अपने को बचाने के लिए कुछ सहारा मिल गया। नीतीश कुमार के राज्यसभा का पर्चा भरने के संबंध में दूसरी खास बात थी, इस मौके पर देश के गृहमंत्री और भाजपा में मोदी के बाद नंबर दो माने जाने वाले, अमित शाह का नीतीश कुमार की बगल में खड़े रहना। इस मौके पर अमित शाह की उपस्थिति एक प्रकार से इसकी याद दिलाने के लिए भी थी कि बिहार की सत्ता में आम तौर पर तथा जदयू में खासतौर पर यह संक्रमण, उनके ही चाणक्य नीति लक्ष्यों के पूरे होने का इशारा कर रहा था। जाहिर है कि खुद अपने हाथों से फैसलों को लागू कराने में विश्वास करने वाले और नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विश्वासपात्र, अमित शाह इस मौके पर खुद उपस्थित रहकर यह तो खैर सुनिश्चित कर ही रहे थे कि भाजपा के मनमाफिक कार्ययोजना बिना किसी दिक्कत के अमल में लाई जाए और उसे जमीन पर उतारने में आखिरी वक्त पर कोई अड़चन नहीं आने पाए। इसी नाटक के दूसरे अंक में, जाहिर है कि पूर्व–योजना के अनुसार, पटना में जदयू कार्यालय में बड़ी धूम–धाम के साथ नीतीश कुमार के पुत्र, निशांत कुमार की राजनीतिक पारी की शुरूआत का ऐलान किया गया। नीतीश कुमार के बाद, जदयू के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले, पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, संजय झा और केंद्रीय मंत्री, ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी। हालांकि, औपचारिक तौर पर यह मौका निशांत कुमार के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का था, लेकिन इसमें न तो निशांत कुमार को कोई शक था और न उन्हें पार्टी का सदस्य बनाने वालों को कि, वास्तव में यह उनके पार्टी का नेतृत्व संभालने का मौका था। इस मौके पर अपने संबोधन में निशांत कुमार ने जिस तरह, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम करने का आश्वासन देने के बाद, पार्टी कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार, पार्टी को मजबूत करने का भरोसा दिलाया, वह पार्टी का नेतृत्व संभालने के मौके के अनुरूप था। और जनता के दिल में घर बनाने की कोशिश करने का उनका आश्वासन तो, यह साफ ही कर देता था कि वह इस आयोजन को पार्टी की गद्दी ही सौंपे जाने के मौके की तरह देख रहे थे। याद दिला दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के, जाहिर है कि भाजपा अनुमोदित पैकेज के हिस्से के तौर पर, निशांत कुमार को बिहार सरकार में महत्वपूर्ण और जदयू की ओर से संभवतरू सबसे महत्वपूर्ण पद सौंपे जाने की चर्चा, पहले ही चल रही थी। इन अनुमानों में आम तौर पर जानकारों की यह राय रही है कि उन्हें उप–मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद भाजपा को दिलवाया जाना तो इस पूरी कसरत का असली मकसद ही है। प्रसंगवश इसका जिक्र भी कर दें कि निशांत कुमार के श्राज्यारोहणश के समय तक, जदयू कार्यकर्ताओं का असंतोष शांत नहीं हुआ था। इस मौके पर भी जदयू कार्यालय में, पार्टी कार्यकर्ताओं के एक हिस्से और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के समर्थकों में, बाकायदा मार–पीट हुई। याद रहे कि जदयू कार्यकर्ताओं का अच्छा–खासा हिस्सा इस सारे बदलाव को, नीतीश कुमार और जदयू के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखता है, जिसे पर्दे के पीछे से केंद्र सरकार तथा भाजपा संचालित कर रही है। केंद्रीय मंत्री, ललन सिंह की जदयू और नीतीश कुमार के प्रति वफादारी पर संदेह जताए जाते रहे हैं। यह भी याद दिला दें कि बिहार में यह सत्ता संक्रमण किसी भी तरह से अप्रत्याशित नहीं है। वास्तव में, पिछले साल राज्य में विधानसभा चुनाव के मौके पर तो लगातार ही विपक्ष की ओर से यह सवाल उठाया जाता रहा था कि क्या भाजपा, चुनाव के बाद गठबंधन के कामयाब होने की सूरत में, अगले पांच साल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगी? विपक्ष ही नहीं, अनेक टिप्पणीकारों के भी इस आशय के सवालों के बावजूद, भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान काफी वक्त तक इस सवाल का स्पष्ट उत्तर देने से बचती ही रही थी। इसके बजाय भाजपा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़े जाने पर जोर देती रही थी, लेकिन इसे विशेष रूप से महाराष्ट्र के अनुभव की रौशनी में, चुनाव में जीत के बाद भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर, संदेह बनाए रखने का ही इशारा माना जा रहा था। पाठकों को याद ही होगा कि महाराष्ट्र में गठजोड़ सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधानसभाई चुनाव लड़े जाने के बाद, विधानसभा में अपनी ताकत ज्यादा होने के तर्क से भाजपा ने, मुख्यमंत्री पद खुद अपने नाम कर लिया था और शिंदे को धकेल कर उप–मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया था। स्वाभाविक रूप से बिहार में पूछा जा रहा था कि यह मानने का क्या आधार है कि भाजपा, महाराष्ट्र के इस पैंतरे को बिहार में भी नहीं आजमाएगी। उल्टे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ते सवालों के बीच, इसकी अटकलों को और बल ही मिल रहा था कि चुनाव में जीत मिली तो भाजपा, अपना मुख्यमंत्री बनवाएगी। वास्तव में ये आशंकाएं बिहार में 2020 के आखिर में हुए चुनाव के नतीजे में, सत्ताधारी जदयू–भाजपा गठजोड़ में ताकतों के संतुलन हुए बदलाव की भी निरंतरता में थीं। यह बिहार में पहली गठजोड़ सरकार थी, जिसमें दो उप–मुख्यमंत्री थे, जो दोनों ही भाजपा से थे। और कार्यकाल के बीच में ही जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर, राजद के साथ गठबंधन सरकार बनाई, वह सरकार तो कुछ महीने ही चली और उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर पल्टी मारकर भाजपा के साथ गठजोड़ में पहुंच भी गए, लेकिन उसके बाद सिर्फ नीतीश कुमार के प्रति भाजपा का अविश्वास ही नहीं बढ़ा था, गठजोड़ सरकार में ताकतों का संतुलन भाजपा ने अपने पक्ष में और भी झुका लिया था। इसके बावजूद, चार महीने पहले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के फौरन बाद, बहुतेरे अनुमानों के विपरीत भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर अधिकार की मांग तो नहीं की, पर उसने सरकार में ताकत का संतुलन और ज्यादा अपने पक्ष में झुका लिया। इसमें विधानसभा के स्पीकर का पद हासिल करने का विशेष रूप से रणनीतिक महत्व था। और अब चार महीने बाद ही भाजपा ने, मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए अपना दांव चल दिया है। फिर भी यह सिर्फ नीतीश कुमार की बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, बीस साल लंबी पारी के अंततरू खत्म होने का ही मामला नहीं है। यह इसका भी मामला नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद जदयू के हाथ से निकलकर, अब भाजपा के हाथ में पहुंच गया है। यह उस दिलचस्प और मारक पैटर्न का हिस्सा है, जो हर जगह क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भाजपा के रिश्तों में देखने को मिलता है। जिन राज्यों में मुख्य राजनीतिक विभाजन, कांग्रेस और उसके विरोध में सामने आयी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच रहा है, उन राज्यों में पांव जमाने के लिए भाजपा, पहले जूनियर पार्टनर के तौर पर इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठजोड़ करती है। उसके बाद, ऐसे हरेक मामले में अरब और उसके ऊंट वाले किस्से को दोहराया गया है, जिसमें ऊंट सर्दी के बचने के लिए थोड़ा–थोड़ा कर के तंबू में घुसने की इजाजत मांगता है और होते–होते होता यह है कि ऊंट तंबू में और अरब तंबू के बाहर। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, असम में असम गण परिषद, जम्मू–कश्मीर में पीडीपी, महाराष्ट्र में शिव सेना का यही अनुभव रहा है।

होली मिलन समारोह 16 मार्च को

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या |जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 16 मार्च को दिन में 12रू00 बजे कांग्रेस कार्यालय कार्यालय कमला नेहरू भवनपर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है |यह जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी।

श्री पाठक ने बताया आगामी 16 मार्च को होने वाले होली मिलन का समारोह कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह वह महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतमके अगुवाई में सम्पन्न होगा |होली मिलन समारोह में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद डॉ निर्मल खत्री,पूर्व विधायक माधव प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा उपस्थित रहेंगे |कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह व महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने समस्त पदाधिकारियों, ए आई सी सी सदस्य,पीसीसी सदस्य, फ्रंटल संगठन प्रकोष्ठों के अध्यक्ष से अपील किया है कि इस होली समारोह में सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हो।

गैस किल्लत को लेकर सदर विधायक ने जिला प्रशासन व आपूर्ति प्रशासन के साथ की समीक्षा

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या |घरेलू गैस की किल्लत को लेकर बुधवार को सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और आपूर्ति अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया |बैठक में जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ गैस आपूर्ति की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक मेंअधिकारियों ने बताया कि जनपद में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, केवल कमर्शियल गैस की आपूर्ति में कुछ दिक्कत आ रही है |उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग न करें |बताया गया कि गैस बुकिंग के बाद अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही संभव होगी |अधिकारियों के अनुसार जिले में प्रतिदिन लगभग 11,200 गैस सिलेंडर की खपत होती है |इसके मुकाबले मंगलवार को 14,670 सिलेंडर और बुधवार को 12,196 सिलेंडर की आपूर्ति हुई |अधिकारियों ने कहा कि घरेलू गैस की सप्लाई लगातार की जा रही है और स्थिति नियंत्रण में है |बैठक में इंडियन आयल और भारत पेट्रोलियम के अधिकारी और डीलर भी मौजूद रहे |बैठक में मौजूद अधिकारियों और डीलरों ने अपनी–अपनी समस्याएं रखीं और गैस आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई |मालूम हो कि इस समय जिले में घरेलू गैस को लेकर उपभोक्ताओं में काफी परेशानी दिखाई दे रही है घरेलू गैस उपभोक्ताओं की भीड़ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित गैस एजेंसी पर भारी संख्या में दिखाई दे रही है |इसके साथ ही साथ जिले के अधिकतर होटल रेस्टोरेंट ढाबे भी कमर्शियल गैस के आपूर्ति न होने के चलते संचालकों के चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है |यहां तक की कुछ होटल रेस्टोरेंट ढाबा के संचालक का कहना है कि अगर इस गंभीर समस्या का शीघ्र ही निराकरण नहीं हुआ और कामर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं हुई तो शीघ्र ही मजबूरी में हम सभी को अपने–अपने होटल रेस्टोरेंट ढाबों को बंद करना पड़ेगा। जिसका असर राम मंदिर का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के साथ–साथ अन्य ग्राहकों पर पड़ेगा।

जिपंअ रोली सिंह व आलोक सीएम से मिले

अयोध्या |जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह व आलोक कुमार सिंह रोहित ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। इस मौके पर उन्होंने अपनी

ग्राम सभा सरायरासी में 19 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित होने वाले श्री राम कथा महोत्सव में कथा श्रवण हेतु आमंत्रित किया।

बहरैची में बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय

भदोही, (संवाददाता)। भदोही तहसील के बहरैची में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय निर्माण के लिए शासन ने 12.50 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। करीब 5.50 एकड़ भूमि में बनने वाले विद्यालय का निर्माण अप्रैल–मई से शुरू हो जाएगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को नामित किया गया है। जिले के दूसरे सीएम मॉडल विद्यालय में विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें करीब दो हजार बच्चों का नामांकन होगा। औराई तहसील का विद्यालय गिर्दबड़गांव में बन रहा है। जिले में 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। कॉन्वेंट विद्यालयों जैसी सुविधा के लिए जिले की तीन तहसीलों में एक–एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनना है। औराई ब्लॉक के गिर्दबड़गांव में स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। भदोही के बहरैची में जमीन चिह्नित की गई थी। अब शासन ने 25 करोड़ की लागत से बनने वाले विद्यालय के लिए आधी धनराशि यानि 12.50 करोड़ जारी कर दिए हैं। बहरैची में जिस स्थान पर विद्यालय बनना है, उसके आसपास अभी गेहूं की फसल है। गेहूं की कटाई के बाद जमीन की पैमाइश कराकर काम शुरू होगा। उम्मीद है कि अप्रैल या मई से काम शुरू हो जाएगा। विद्यालय में कक्षा एक से 12 तक की कक्षाएं चलाई जाएंगी। ज्ञानपुर के घरांव में जमीन का चयन किया जा चुका है। बीएसए शिवम पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय तीनों तहसीलों में बनना है। औराई के गिर्दबड़गांव में काम चल रहा है। बहरैची के लिए पैसा जारी हो गया है। बहरैची में बनने वाले विद्यालय पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

लोभ और लालच रखने से नहीं हो सकेगी ईश्वर की प्राप्ति – माता कृष्णा

भदोही, (संवाददाता)। काली माता मंदिर परिसर में आयोजित सात दिवसीय कथा में रविवार की शाम कथा व्यास पूज्य संत माता कृष्णा ने आध्यात्मिक संदेश देते हुए जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया। कहा कि जहां लोभ, लालच, ईर्ष्या और द्वेष होता है, वहां ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं होती। उन्होंने कहा कि मनुष्य का सुख और दुख दोनों ही उसके मन पर निर्भर करते हैं। यदि मन शुद्ध और शांत है तो जीवन में सुख की अनुभूति होती है, जबकि अशांत मन दुख का कारण बनता है। कहा कि जो व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त है। वही सच्चा संत है। जो स्वयं ही मोह और बंधन में जकड़ा है। वह दूसरों को मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण कर लेता है।

ईरान में फंसे भारतीय के परिजनों में दहशत वतन वापसी की सरकार से लगा रहे गुहार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,11 मार्च। ईरान इजराइल और अमेरिका में हो रहे युद्ध के बीच कई भारतीय अलग अलग खाड़ी देशों में फंसे हुए है |जो अपनो के बीच वतन वापसी करना चाहते है,लेकिन भीषण जंग के कारण अभी तक वतन वापसी नही हो पाई है |खाड़ी देशों में फंसे हुए लोगो के परिवारीजन इसको लेकर काफी चिंतित है और भारत सरकार से अपनो की वतन वापसी की गुहार लगा रहे है |इसी क्रम में यूपी के जौनपुर जिले के लाइन बाजार क्षेत्र के रामदासपुर नेवादा निवासी शुभम जायसवाल ईरान के अर्दकन शहर में फंसे हुए है,वह ईरान की तारा स्टील कंपनी में लैब टेक्नीशियन के पद पर नौकरी कर रहे थे। बुधवार को देश की उपासना ब्यूरो से बात करते हुए शुभम के बड़े भाई मोहित जायसवाल ने बताया कि छोटा भाई शुभम चार वर्ष पूर्व नौकरी के लिए ईरान गया था,अभी पिछले साल फरवरी 2025 में भारत अपने घर आया था |लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से वापस चला गया। मोहित ने बताया कि शुभम जल्द ही भारत लौटने की तैयारी में था और फ्लाइट की टिकट भी कन्फर्म हो गयी थी |लेकिन इसी बीच इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया |तब से वह वहीं फंसा हुआ है,मोहित ने बताया कि वहां शुभम के साथ 40 से ज्यादा भारतीय फंसे है जो उसी स्टील कंपनी में कार्य करते है। मोहित जायसवाल ने बताया कि कल यानी मंगलवार को भी शुभम से बातचीत हुई है लेकिन वहां का मंजर बहुत भयावह है,शुभम ने बातचीत में अपने परिवार से बताया कि एक एक कर सभी शहर नष्ट होते जा रहे है,हमारी आंखों के सामने से मिसाइल निकलती है |यहां बहुत डर का माहौल है |शुभम ने ईरान में भारतीय दूतावास से सम्पर्क किया है लेकिन वहां भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। ईरान में फंसे शुभम के भाई मोहित ने भारत सरकार से अपील किया है कि मेरे भाई के साथ ईरान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी कराई जाए।

उत्तर मध्य क्षेत्र की सांस्कृतिक प्रतियोगिता में चमके डीडीयू के शिक्षक व छात्र

गोरखपुर, (संवाददाता)। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से श्विकसित भारत के रंग, कला के संगश् विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पेशेवर वर्ग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. गौरीशंकर चौहान व छात्र वर्ग में अभिषेक पासवान विजेता रहे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से यह प्रतियोगिता 17 सितंबर से दो अक्तूबर

2025 तक आयोजित थी। इसके विजेताओं को आठ मार्च को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज में सम्मानित किया गया। प्रोफेशनल वर्ग में डीडीयू के ललित कला एवं संगीत विभाग के डॉ. गौरीशंकर चौहान को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये का चेक व प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। ललित कला विभाग के ही डॉ. प्रदीप साहनी को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार का चेक व प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। कॉलेज वर्ग की प्रतियोगिता में ललित कला विभाग के छात्र अभिषेक पासवान को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 25 हजार रुपये एवं प्रमाणपत्र और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले शिवम कुमार गुप्ता को 15 हजार रुपये एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का बेजोड़ परिचय दिया है। इस उपलब्धि पर विभागाध्यक्ष प्रो. उषा सिंह, डीएसडब्ल्यू प्रो. अनुभूति दुबे आदि ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।

यूपी में गेंहू व उत्पादों के 1600 करोड़ के निर्यात पर युद्ध का साया, तीन साल बाद मिला था मौका सौदे रद्द

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में तीन साल बाद शुरू होने जा रहे गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों (आटा, मैदा, सूजी) के निर्यात पर पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध का साया पड़ गया है। भारत सरकार ने 2026 में सीमित मात्रा में गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम, बीमा लागत और शिपिंग संकट के कारण खाड़ी देशों को होने वाला निर्यात फिर से अनिश्चितता में घिर गया है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के गेहूं व्यापार और मिलिंग उद्योग पर पड़ा है। निर्यातक संगठनों के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने और युद्ध जोखिम बीमा के महंगे होने से कई नए निर्यात सौदे फिलहाल टाल दिए गए हैं। भारत सरकार ने फरवरी 2026 में 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात को मंजूरी दी थी। यह कदम 2022 में लगे प्रतिबंध के बाद निर्यात को आंशिक रूप से फिर खोलने

जैसा था। सरकार का मानना था कि बेहतर उत्पादन और पर्याप्त भंडार के कारण यह निर्यात किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद करेगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव और यूपी रोलर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक बजाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों में है। यहां आटा–मैदा मिलों का बड़ा नेटवर्क है। गेहूं आधारित उत्पादों के निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 25–35 प्रतिशत तक है। उन्होंने कहा कि यूपी से ही 1500 से 1700 करोड़ रुपये का निर्यात के दरवाजे खुल गए थे। इनका सबसे ज्यादा लाभ गेहूं आधारित प्रोसेसिंग और निर्यात के प्रमुख नेटवर्क क्षेत्र कानपुर, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली सहित कम से कम 20 जिलों को मिलता। इन क्षेत्रों की मिलें खाड़ी देशों यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और कतर में आटा, मैदा और सूजी की आपूर्ति करती रही हैं। आशंका जताई कि यदि युद्ध जारी रहा तो शिपिंग लागत 40–50: तक और बीमा प्रीमियम दोगुना हो सकता है। ऐसे में तीन साल बाद खुलने जा रहा निर्यात बाजार में उत्तर प्रदेश के आटा–मैदा उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि

लखनऊ, । उत्तर प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों और पंचायती राज विभाग की प्रभावी कार्यशैली के चलते स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रथम और द्वितीय चरण में प्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रथम चरण में प्रदेश को 100 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया जा चुका है, जो ग्रामीण स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और जनसहभागिता का परिणाम माना जा रहा है |योजना के दूसरे चरण में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखने के साथ–साथ स्वच्छता को और मजबूत बनाने की दिशा में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में प्रदेश के 95 हजार 767 गांवों ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के साथ स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है, जबकि 94 हजार 723 से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति बढ़ती जागरूकता और बेहतर प्रबंधन को दर्शाती है |स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रदेश में 2 करोड़ 74 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण सफलतापूर्वक कराया गया। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक शौचालय निर्माण करने वाला राज्य बनकर उभरा है। वहीं मिशन के द्वितीय चरण के तहत अब तक 57 लाख 25 हजार 291 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है।

'आंगनबाड़ी केंद्रों के शौचालयों को विशेष रूप से साफ-सुथरा' 'रखें-सीडीओ'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' बुधवार को जिला पोषण समिति के तहत जनपद के आंगनबाड़ी केन्द्रों की व्यवस्थाओं एवं कुपोषित बच्चों के कार्यो सम्बन्धी समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी सान्या छावड़ा की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानन्द सभागार कलेक्ट्रेट में आहूत की गयी। उन्होंने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिये कि आंगनबाड़ी केंद्रों के शौचालयों को विशेष रूप से साफ–सुथरा रखें और नियमित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कार्यो की समीक्षा करें तथा कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही करें।

बैठक में लक्ष्य के अनुरूप ब्लाक कोथावां, कछौना, हरपालपुर, टड़ियावा व भरखनी की सीडीपीओ द्वारा अति कुपोषित बच्चों को भर्ती न कराने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिये कि अति कुपोषित बच्चों को चिकित्सों की देखरेख में तत्काल एनआरसी पर भर्ती करायें और लक्ष्य के तहत अधिक से अधिक बच्चों को ग्रीन श्रेणी में लाएं तथा निर्धारित समय सीमा में सभी पात्र महिलाओं एवं बच्चों में पोषाहार वितरण करायें। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं सीडीपीओ आदि उपस्थित रहे।

चौकिया धाम मार्गो के चौड़ीकरण को 9.66 करोड़ की मंजूरी, आवागमन होगा सुगम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जनपद में विकास कार्यों को गति देते हुए प्रदेश सरकार ने तीन प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 966.62 लाख रुपये (लगभग 9.66 करोड़ रुपये) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025–26 की धर्मार्थ योजना के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण कार्यों को मंजूरी दी है। ये स्वीकृति खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव के प्रयासों का परिणाम है। लंबे समय से इन मार्गों के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी, जिसे अब शासन स्तर से स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत तीन प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इनमें जौनपुर–आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 120ए के किलोमीटर 59 से चौकिया

धाम मंदिर तक का मार्ग, चौकिया–आरा मार्ग के किलोमीटर 1 से चौकिया धाम मंदिर तक का मार्ग तथा जौनपुर–आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 128ए के किलोमीटर 58 से श्री चौकिया धाम मंदिर तक का मार्ग शामिल है। इन सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से माता शीतला धाम चौकियां मंदिर क्षेत्र में आवागमन की व्यवस्था और बेहतर होगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, साथ ही स्थानीय लोगों को भी यातायात में राहत मिलेगी। इसके अलावा इन मार्गों के विकास से आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और चौकिया धाम आने–जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी।

कमर्शियल गैस सिलेंडर की दिक्कत लेकिन घरेलू की नहीं - डीएसओ

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या |जिले में गैस सिलेंडर को लेकर लगातार जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग अपनी मानिटरिंग कर रहा है |इस संबंध मे जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार मिश्र ने बताया कि बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता के सम्बन्ध में बैठक हुई है जिसमें एडीएम (नगर) योगानंद पांडेय, एसपी नगर चक्रपाणि त्रिपाठी विभिन्न कंपनियों के सेल्स ऑफीसर (आई०ओ०सी०एल०) एवं नगर निगम, अयोध्या के गैस एजेन्सी धारक शामिल रहे। समीक्षा करने पर ऑयल कम्पनी के सेल्स ऑफीसर द्वारा बताया गया कि जनपद में तीनों ऑयल कम्पनी (आई०ओ०सी०एल०६ बी०पी०सी०एल०ध्एच०पी०सी०एल०) की कुल 55 गैस एजेन्सियाँ कार्यरत हैं,जिसमें 10 मार्च को 12504 एवं 11 मार्च को 12196 घरेलू कुकिंग गैस सिलेण्डरों की उपलब्धता है |जबकि जनपद की दैनिक मॉग 11200 गैस सिलेण्डर है। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर की कोई समस्या नहीं है |19 कि०ग्रा० के कामर्शियल गैस सिलेण्डरों की आमद भारत सरकार द्वारा रोक दी गयी है। जिसके कारण होटलों ६ प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक भण्डारों आदि स्थानों पर 19 कि०ग्रा० के कामर्शियल गैस सिलेण्डरों की समस्या विद्यमान है |डीएसओ ने बताया कि डीएम के निर्देश पर समस्त गैस एजेन्सियों को निर्देशित किया गया कि एजेन्सी पर गैस का निर्धारित मूल्य के सम्बन्ध में फ्लैक्स प्रदर्शित करें व अगले दिवस में जिन उपभोक्ताओं को गैस की डिलीवरी होनी है उनकी सूची गैस एजेन्सी पर चस्पा की जाये जिससे एजेन्सी पर अनावश्यक रूप से भीड न लगने पाये तथा इस आशय की आडियो रिकार्डिंग चलायी जाय कि गैस डिलीवरी के उपरान्त 25 दिन के पश्चात ही ऑन लाइन बुकिंग होगी तथा शहरी क्षेत्र अयोध्या में गैस की होम डिवीवरी गैस बुकिंग के 48 से 72 घण्टे की अन्दर की जाएगी |डीएम द्वारा नोडल अधिकारी एल०पी०जी० को निर्देशित किया गया कि डिलीवरी ६ बुकिंग सम्बन्धी उपर्युक्त मैसेज उपभोक्ताओं के मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कराया जाय। घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग कामर्शिलय सिलेण्डर में न किया जाय |घरेलू सिलेण्डरों का दुरूपयोग पाये जाने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी |डीएम ने एसपी सिटी को गैस एजेन्सियों पर भीड़ की स्थिति में आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग के सशक्तीकरण के लिए योजनाओं की समीक्षा

लखनऊ, (संवाददाता)। योगी सरकार दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध और परिणामोन्मुखी तरीके से कार्य कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को सचिवालय स्थित नवीन भवन में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, वित्तीय उपलब्धियों और लाभार्थियों तक पहुंच की स्थिति का आकलन किया गया |बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचे और इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ये दोनों विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं और इन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडल स्तर पर कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम और प्रचार अभियान चलाकर इन विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक सुविधाओं, पाठ्यक्रमों और अवसरों की जानकारी दिव्यांग छात्रों तक पहुंचाई जाए। साथ ही दोनों विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने और निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय–सीमा में पूरा कराने के निर्देश भी दिए |पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि योजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना तभी तय होता है ।

धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे संत आसाराम बापू

अयोध्या। धर्मनगरी के प्रमुख मंदिरों में पहुंचकर संतों के साथ दर्शन–पूजन किया।मंदिर निर्माण के बाद यह उनका पहला अयोध्या दौरा बताया।राम मंदिर अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन की बात कही।हनुमान गढ़ी में पूजा–अर्चना करने भी पहुंचे।कहाकृभारत की आध्यात्मिक शक्ति ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत में सात मोक्ष स्थलों के महत्व को पूरे विश्व में अद्वितीय बताया। आयुर्वेद का उल्लेख करते हुए शरीर के तीन दोषकृवात, कफ और पित्त की जानकारी दी। सरयू आरती के दौरान देश की सुख–समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की।

दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट एवं छिनौती के मामले में अदालत ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। थाना बाबाबाजार क्षेत्र के ग्राम महमूदमऊ में को शाहिद नसीम पुत्र मोहम्मद नईम जो अपने निर्माणाधीन भवन के पास निर्माण सामग्री लेकर गए थे।जहां पर गांव के ही मोहम्मद वैस,शादाब,अनस, हंजला, बिलाल द्वारा की गई मारपीट के संबंध में न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।महमूदमऊ निवासी शाहिद नसीम ने अपने अधिवक्ता अरशद शेरा को बताया गया कि गांव के ही उक्त विपक्षीगण ने गांव की गुटबाजी एवं पुरानी रंजिश को लेकर विगत तिथि को मुझे जान से मारने की नीयत से मेरे निर्माणाधीन मकान पर आकर आमादा फौजदारी होकर गलियां देने लगे।पीड़ित डरकर घर के अंदर भाग गया विपक्षी गण घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट एवं छिनैती की। जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित के द्वारा थाना बाबाबाजार में की गई परन्तु कोई सुनवाई न होने पर अपने वकील अरशद शेरा के माध्यम से 173(4) बी एन एस एस के अंतर्गत अदालत का दरवाजा खटखटाया जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।मुकदमा की पैरवी अधिवक्ता अरशद शेरा द्वारा की गई।

मवई पुलिस ने 79,779 रुपये की धनराशि को कराया वापस

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। मवई पुलिस साइबर फ्रॉड में खाते से गये 79,779/- रुपये की धनराशि को वापस कराया गया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ कुशल मार्गदर्शन में एवं एसपी ग्रामीण ध्नोडल अधिकारी साइबर क्राइम बलवंत चौधरी व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के नेतृत्व में साइबर अपराधियों व साइबर अपराध की घटनाओं पर अंकुश एवं साइबर जागरुकता कार्यक्रम किये जाने के क्रम में थाना मवई जनपद अयोध्या पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के एनसीआरपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायत ।क्व्ल.छ्द्द 33101260016173 जिसमें शिकायत कर्ता द्वारा तीन पत्ती गेम सोना ऐप इंस्टाल किये जाने के कारण शिकायतकर्ता का मोबाइल हैक करके खाते से रुपये ट्रान्सफर कर लेने सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए फ्रॉड में गई कुल धनराशि– 79779/- रुपये को शिकायत कर्ता के खाते में वापस कराया गया।इस सरहानीय कार्य में सुरेश कुमार पटेल थानाध्यक्ष थाना मवई के साथ उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव थाना मवई की मुख्य भूमिका रही। इस संबंध में साइबर क्राइम नोडल प्रभारीध्एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने लोगो से अपील किया कि वे साइबर अपराधों से सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या लिंक पर विश्वास न करें और धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा cybercrime-gov-in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

विद्युत विभाग ने कुल 68418 उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाते हुये जमा कराये 60.72 करोड़ रुपये

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० द्वारा उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने हेतु 01 दिसम्बर 2025 से श्बिजली बिल राहत योजना 2025–26श शुरू की थी। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो जिसके तहत 3 चरणों में उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में लाभ दिया जा रहा है।तीनों चरणों में बिजली बिल पे लगे ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट थी। तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में मूल धन पर क्रमशः 25:, 20: एवं 15: तक की छूट अनुमन्य की गयी थी। इस योजना में बिजली बिलों के अलावा ऐसे मामलों में भी छूट का प्रावधान किया गया था जिसमे चोरी का जुर्माना उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना था।योजना का लाभ जन–जन तक पहुँचाने हेतु विद्युत विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर योजना का प्रचार–प्रसार किया गया तथा ग्राम स्तर तक कैम्पों का आयोजन भी किया गया।इस संबंध मे अधिशासी अभियंता वैभव आनंद ने बताया कि इस योजना का लाभ लेते हुये जिला अयोध्या में कुल 68418 उपभोक्ताओं ने रूपये 60.72 करोड़ जमा किये तथा विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के बिलों का 53.79 करोड़ रूपये माफ किया गया।इस योजना का लाभ लेते हुये विद्युत बिल जमा करने वालों में 14,654 उपभोक्ता ऐसे थे,जिनके द्वारा कभी विद्युत बिल जमा नही किया गया था तथा 53,764 उपभोक्ता ऐसे थे जिनके द्वारा मार्च 2025 के उपरान्त अपने विद्युत बिलों का भुगतान नही किया गया था।बिजली चोरी के मामलों में जिला अयोध्या में योजना का लाभ लेते हुये कुल 799 उपभोक्ताओं ने रूपये 1.59 करोड़ जमा किये। उत्तर प्रदेश सरकार की इस जन–कल्याणकारी योजना को विद्युत विभाग ने सफल बनाते हुये आम जनमानस को अत्याधिक राहत प्रदान की गयी।

मुख्य विकास अधिकारी ने जन सनुवाई में सुनी 67 शिकायतें'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' बुधवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान मुख्य विकास अधिकारी सान्या छावड़ा ने आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में कुल 67 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो। जनसुनवाई में प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

सिलेंडर संकट के बीच अमावरम मंदिर रसोई,10–12 हजार लोगों को मिल रहा भोजन – पंकज

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।देश में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर उत्पन्न संकट के बीच भी अमावरम मंदिर की रसोई सेवा निरंतर जारी है। यह रसोई पटना के महावीर मंदिर पटना से संचालित होती है और इसकी शुरुआत मंदिर के संस्थापक रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल के संकल्प से की गई थी। मंदिर की रसोई की वर्तमान व्यवस्था देख रहे पंकज जी ने बताया कि सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ जरूर आई हैं। उन्होंने कहा कि देश–दुनिया की परिस्थितियों और युद्ध जैसे हालात के कारण गैस सिलेंडर की कमी का असर यहाँ भी पड़ा है उन्होंने बताया कि पहले प्रतिदिन लगभग 20 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन सिलेंडर संकट के कारण फिलहाल करीब 10 से 12 हजार लोगों को ही भोजन कराया जा पा रहा है पंकज जी ने यह भी स्पष्ट किया कि अमावरम मंदिर की रसोई बंद होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। रसोई पहले की तरह ही चल रही है और आगे भी चलती रहेगी उन्होंने कहा कि यदि सिलेंडर की आपूर्ति समय पर नहीं होती है तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार की जा रही है। जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक उपकरणों और कोयले के माध्यम से भोजन बनाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि सेवा का यह संकल्प किसी भी परिस्थिति में बाधित न हो मंदिर प्रबंधन का कहना है कि जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना उनका संकल्प है और इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा।

डीएम ने जनता दर्शन में सुनी फरियादियों की समस्याएं

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।डीएम निखिल टीकाराम फुंडे की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। जनता दर्शन में शहर क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के भी फरियादी आए यहां पर आए फरियादियों की समस्याओं को डीएम ने गंभीरता से सुना। इन समस्याओं को उन्होंने सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये।जनता दर्शन में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व संबंधित प्रकरण, पेंशन, विद्युत, जलापूर्ति, सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधा तथा जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दे सामने आए।डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए और शिकायतकर्ता को निस्तारण की जानकारी समय से उपलब्ध कराई जाए।

'डीएम एवं एसपी की अध्यक्षता में आगामी अलविदा व ईद पर्व को लेकर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी बैठक आयोजित'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' आगामी अलविदा तथा ईद के त्योहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईदगाह कमेटी के सदस्य, धर्मगुरु तथा शहर के संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बताया गया कि 13 मार्च, शुक्रवार को जनपद की विभिन्न मस्जिदों सहित ईदगाहों में अलविदा की नमाज अदा की जाएगी तथा इसके उपरांत आगामी दिनों में ईद के अवसर पर ईद की नमाज का आयोजन जनपद की सभी मस्जिदों में किया जाएगा। अलविदा की नमाज रमजान माह के अंतिम शुक्रवार को अदा की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में नमाजी शामिल होते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। बैठक में ईदगाह कमेटी के सदस्यों एवं धर्मगुरुओं ने अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। उन्होंने मस्जिदों एवं ईदगाहों के आसपास साफ–सफाई की व्यवस्था, छुट्टा पशुओं को नियंत्रित करने, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल की समुचित व्यवस्था तथा नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त जिन स्थानों पर सड़कें खुदी हुई हैं, वहां धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव कराए जाने की भी मांग रखी गई। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि जनपद की प्रमुख मस्जिदों तथा ईदगाह, जामा मस्जिद के पहुंच मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा आसपास साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चूना छिड़काव कराने के भी निर्देश दिए । जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि अलविदा के दिन सड़कों पर छुट्टा पशु न घूमने पाए इसके लिए नगर निगम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही डेयरी संचालकों को भी निर्देशित किया जाए कि अलविदा के दिन अपने पशुओं को सड़कों पर न निकालें, जिससे आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि नमाज के समय किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए साथ ही शहर पेश इमाम हुजूर अहमद मंजरी से कहा कि किसी भी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कॉल करके समस्या से अवगत करा सकते हैं। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे रमजान अलविदा एवं ईद का त्योहार जनपद में आपसी सौहार्द, शांति एवं भाईचारे के वातावरण में संपन्न हो सके। बैठक के दौरान नगर आयुक्त डॉ विपिन कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र , अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार, एसपी ग्रामीण सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

राम जन्मभूमि मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में ठीक 11:55 पर होगी श्री रामयंत्र की स्थापना

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।राम जन्मभूमि मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में ठीक 11:55 पर श्री रामयंत्र की स्थापना की जायेगी।19 मार्च को वैदिक मंत्रोचार के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11:55 पर अभिजीत मुहूर्त मे श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना करेंगी।राष्ट्रपति सुबह 11:00 बजे राम मंदिर पहुंचेंगी इसके बाद परिसर के सभी उप मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगी। उसके बाद राम मंदिर के दूसरे तल पर श्रीराम यंत्र की स्थापना करेंगी।12:45 से 2:15 तक राष्ट्रपति समेत अन्य अतिथियों का संबोधन होगी।संबोधन के बाद कार्यक्रम में शामिल सभी मेहमानों को रामलला के कराए दर्शन करायेगे।समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमृतानंदमयी, वीरेंद्र हेगड़े संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले शामिल होंगे। श्रीराम यंत्र की स्थापना के लिए काशी, दक्षिण भारत व अयोध्या के कुल 51 आचार्य मौजूद रहेंगे।समारोह में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से 5000 से अधिक मेहमानों को बुलाया गया है।मेहमानों में मंदिर आंदोलन के कारसेवक भी शामिल होंगे।

वरिष्ठ व्यापारी एवं स्थानीय पत्रकार राजकुमार जायसवाल के पिता जगदम्बा प्रसाद जायसवाल का हृदयाघात से निधन : शोक की लहर

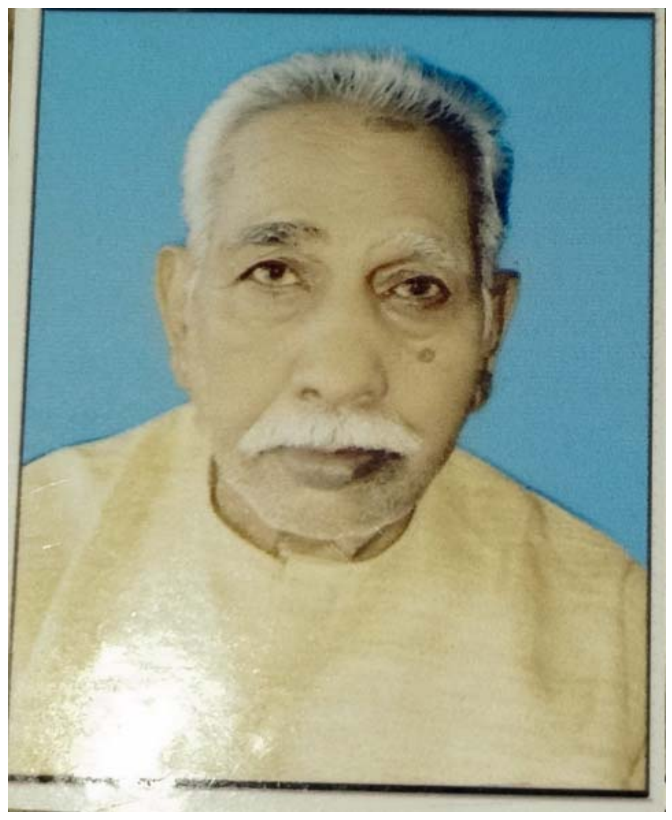

देश की उपासना ब्यूरो

आजमगढ़ रूबिलरियागंज कस्बे में मंगलवार को वरिष्ठ व्यापारी एवं स्थानीय पत्रकार राजकुमार जायसवाल के पिता जगदम्बा प्रसाद जायसवाल का हृदयाघात से निधन हो गया। वह लगभग 85 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर मिलते ही कस्बे समेत आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी और परिजनों में कोहराम मच गया।

बताया जाता है कि जगदंबा प्रसाद जायसवाल गल्ला के थोक व्यवसाय से जुड़े हुए थे और क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यापारी के रूप में उनकी पहचान थी। उनका स्वभाव बेहद सरल, मिलनसार और हंसमुख था, जिसके कारण वे समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय थे। उनके अचानक निधन से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। मृतक अपने पीछे चार पुत्रों का भरा–पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके सभी पुत्र विवाहित हैं और अपने–अपने व्यवसाय में संलग्न हैं। पिता के निधन से परिवार के सदस्यों का रो–रोकर बुरा हाल है।

सोमवार को रात्रि निधन मंगलवार की दोपहर उनका अंतिम संस्कार मऊ जनपद के दोहरीघाट स्थित मुक्तिधाम पर पूरे विधि–विधान के साथ किया गया, जहां परिजन, रिश्तेदार, शुभचिंतक और क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इधर, उनके आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।

धूम्रपान निषेध दिवस पर मिल्कीपुर विधायक व सीएमओ ने फीता काटकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। बुधवार को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अयोध्या में क्षय रोग पर आधारित पोषण पोटली वितरण एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी माह मार्च के द्वितीय बुधवार 11 मार्च 2026 को धूम्रपान निषेध दिवस (नो स्मोकिंग डे) का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोष्ठी एवं शपथ का आयोजन मिल्कीपुर विधायक चन्द्रभान पासवान की अध्यक्षता में किया गया।विधायक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।इस अवसर पर विधायक को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भगवान राम के नाम की पट्टिका देकर स्वागत किया।इस अवसर पर विधायक ने लोगो को तम्बाकू न प्रयोग करने की शपथ दिलायी।उसके बाद सम्बोधन में विधायक ने बताया कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की सरकार आप जनमानस से अपील करता है कि नशे का सेवन न करें, जिसको भी टीबी का लक्षण दिखायी दे वह बलगम जांच, एक्स–रे कराकर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में निःशुल्क इलाज प्राप्त करें।मुख्य चिकित्साधिकारी डा० देवेन्द्र कुमार भिटौरिया ने जनमानस को बताया कि जनपद में 15 टीवी यूनिट एवं 33 डी०एम०सी० उपलब्ध है और सभी सभी स्वास्थ्य केन्द्रों जांच व इलाज निःशुल्क उपलब्ध हैं।जिला क्षय रोग अधिकारी डा० संदीप कुमार शुक्ला ने टीवी के लक्षण व जांच के सम्बन्ध में विस्तार से बताया शासन के द्वारा क्षय रोगियों को

प्रतिमाह रु0 1000.00 पोषण हेतु डी०बी०टी० के माध्यम से दिया जाता है। टीबी के मरीजों की जांच व दवा सभी स्वास्थ्य केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध है।जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा बताया गया कि फेफड़े के मरीज के साथ रहने वाले सभी लोग टीबी की बीमारी के लिये नार्मल व्यक्ति की तुलना में कई गुना टी०बी० होने की सम्भावना रहती है। फेफड़े की टीबी के साथ साथ रहने वाले अपनी आशा व सी०एच०ओ० व पी०एच०सी० ६ सी०एच०सी० पर निःशुल्क एक्स–रे एण्ड बलगम की जांच कराकर टीबी से बचाव की दवाओं को निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। विधायक ने पोषण पोटली वितरण किया।विधायक,मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला क्षयरोग अधिकारी, अधीक्षक मिल्कीपुर एवं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर अवधेश शर्मा ने 10–10 मरीजों को निक्षय मित्र बनकर 10–10 मरीजों को गोद लेकर पोषण पोटली का वितरण किया।इस कार्यक्रम में कुल 50 मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया गया।कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मण्डल अध्यक्ष श्याम नारायण पाठक, डा० पी०सी० भारती उपमुख्य चिकित्साधिकारी, डा० ए०के० सिन्हा अधीक्षक, सामु० स्वा०केन्द्र मिल्कीपुर, श्री सचिन गुलाटी, जिला प्रबंधक, डब्लू०एच०पी०, अनिल कुमार एस०टी० एल०एस०, अनिल कुमार सिंह मेला सहायक, श्री राम अनुज सिंह एवं मिल्कीपुर के सभी स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बोर्ड परीक्षा दिलाने जा रहे भाई की सड़क हादसे में मौत, बहन घायल

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोला थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह बहन को बाइक से बोर्ड परीक्षा दिलाने जा रहे 18 वर्षीय युवक अनीस गौड़ की हादसे में मौत हो गई जबकि उसकी बहन समेत दो लोग घायल हो गए। हादसा गोल–उरुवा मार्ग पर चंदौली गांव के पास दो बाइकों की आमने–सामने टक्कर से हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। वहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। गोला इलाके के बेलपार पाठक गांव निवासी अनीस गौड़ सोमवार सुबह करीब सात बजे अपनी बहन श्रेया गौड़ को इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा दिलाने के लिए बड़हलगंज क्षेत्र के एक विद्यालय लेकर जा रहा था। जैसे ही दोनों चंदौली गांव के पास पहुंचे, सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में अनीस गौड़, उसकी बहन श्रेया गौड़ और दूसरी बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।